2. State Governments have also agreed to reserve certain percentages of vacancies in their Class I and Class II (Non-technical) posts for released ECOs.

3. Relaxation in educational qualifications has been allowed to the ECOs/SSCOs whose studies were interrupted due to their having joined the Army with the consequence that they could not acquire the requisite minimum educational qualification of a Degree for appointment to the civil services.

4. For released ECOs/SSCOs holding Engineering Degrees, 32% of vacancies in Class I & Class II Services had been reserved. This has since been reduced to 27%, due to raising the reservation for SC/ST. Selection of candidates is made on the basis of technical interview by the UPSC instead of their having to sit for a written examination.

5. ECOs who have risen from the ranks and have not been found fit for grant of Permanent Commission are considered for reversion, at least to JCO's rank, on a purely voluntary basis, and each case of such reversion is examined on merits.

6. The State Governments have been requested to extend all facilities including finance, technical know-how, raw materials, etc. to released emergency commissioned officers in their efforts to organise co-operatives in the industrial sector.

7. Guidance for set ing up Small Industries as a measure of self-employment of released ECOs, in industrial estates, in agriculture etc., is being given to them by an officer specially appointed for this purpose under the Directorate General of Resettlement of this Ministry.

8. To help the ECOs, a number of re-orientation courses in the field of Business, Industrial and Personnel Management have been arranged. 219 ECOs have so far undergone such courses.

9. Efforts are being made to persuade the Public Sector Undertakings under the various Central Government Departments to absorb the released ECOs. Such efforts are also being made with the Private Sector Undertakings by the officers on Special Duty at Delhi, Calcutta and Bombay, under the Directorate General of Resettlement in this Ministry.

10. State Bank of India has reserved 25% of the vacancies in the officers' cadre for the released ECOs. The Ministry of Finance have been requested to advise the Managements of the other nationalised banks to set apart 25% vacancies in the Junior officers' cadre, exclusively for the released ECOs as has been done by the State Bank. The matter was to be placed before the Co-ordination Committee of the Custodians of the Public Sector Banks.

11. Survey-trained released ECOs are being considered for appointment in the Survey of India in a civilian capacity, in consultation with the UPSC.

12. A scheme has been introduced under which interest free loan upto Rs 2,000/- would be sanctioned to individual ex-Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officers for undergoing the following training/higher educational studies within the country :

(a) Professional training

(b) Management training

(c) Educational studies qualifying for a degree or above.

बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के खान मालिकों पर रायल्टी की बकाया राशियां

14. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम, रसायन तथा अलोह धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों के खान मालिकों पर राज्यवार राज्य सरकारों की रायल्टी की कितनी राशि बकाया है ;

(ख) इस सम्बन्ध में उक्त धनराशि की वसूली के लिए (राज्य सरकारों द्वारा) राज्यवार

की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इस बारे में कोई निदेश जारी किए है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा अलोह धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). राज्य सरकारों से जानकारी की अपेक्षा की गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रखी जायेगी ।

(ग) जी नही ।

(घ) प्रश्न नही उठता है ।

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास के लिए राज्य सरकारों को अनुदान

15. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास कार्यक्रमो के लिए अनुदान प्रदान करती है ;

(ख) यदि हां, तो बिहार राज्य की सरकार को 1967 से 1970 तक वर्षवार दिए गए अनुदानों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मजूर की गई राशि के सम्बन्ध में और मकानों के नियतन मे गम्भीर अनियमितताएं की गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी अनियमितताओं को रोकने के उद्देश्य से सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री, (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) अनुदान (सहायता) निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मन्त्रालय द्वारा आरम्भ की गई विभिन्न प्रकार की चार निम्नलिखित सामाजिक आवास योजनाओं के लिए उपलब्ध है :—

(i) औद्योगिक कर्मचारियों तथा समुदाय के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना ।

(ii) बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना ।

(iii) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम ।

(iv) गन्दी बस्ती हटाओ तथा सुधार योजना ।

सिवाए ऊपर (ii) पर की योजना को छोड़, ये सभी योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं और बिहार में चालू है ।

1968-69 के अन्त तक सभी सामाजिक आवास योजनाओ के लिए केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों द्वारा, योजना के अनुमोदित व्यय के अनुसार, उनके वास्तविक व्यय के आधार पर ली जा रही थी । 1967-68 और 1968-69 के दौरान बिहार सरकार को स्वीकृत किए गए केन्द्रीय "अनुदान" नीचे दिए जाते हैं :—

	1967-68	1968-69
	(लाख रुपयों मे)	
(क) औद्योगिक कर्मचारियों आदि के लिए एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना,	4.00	3.14